Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 GISRRJ | Volume 4 | Issue 4 | ISSN : 2582-0095

भारत में कारोबारी विकास के रुझान

दीक्षा आर्य
असिस्टट प्रोफेसर, आसिम सिद्दीकी मेमोरियल डिग्री कॉलेज, बदायूं,उत्तर प्रदेश।

Article Info
Volume 4 Issue 4
Page Number : 54-62

Publication Issue :
July-August-2021

Article History
Accepted : 02 July 2021
Published :18 July 2021

शोधसार– ऐसा कहा जाता है कि 'सफल प्रबंधकों की कुंजी भविष्य की आर्थिक संभावनाओं की महत्वपूर्ण जागरूकता और दृष्टि पर निर्भर करती है'। आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में, फर्मों को निर्णय लेने होते हैं और उन कारकों पर ध्यान देना पड़ता है जिनके वे नियमित रूप से संपर्क में आते हैं। सभी कारकों और ताकतों का समूह जो किसी संगठन के अपने उद्देश्यों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित करता है, उसे ''व्यावसायिक वातावरण'' कहा जाता है। सफल फर्म वे हैं जो ऐसे पर्यावरणीय कारकों में परिवर्तन पर ध्यान देती हैं और अपने संगठनों में उपयुक्त परिवर्तन करती हैं। वर्तमान पेपर भारतीय अर्थव्यवस्था में कारोबारी माहौल में बदलाव की जांच करने का प्रयास करता है। व्यावसायिक वातावरण के कारक प्रत्येक व्यवसाय की सफलता को प्रभावित करते हैं। एक सफल व्यवसायी वह है जो इन बदलते कारकों की पहचान करता है, समझता है और प्रतिक्रिया करता है। इसलिए, यह समझना आवश्यक हो जाता है कि ये परिवर्तन क्या हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था में एक विशाल छलांग के लिए तैयार है। हाल के चुनावों में नरेंद्र मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत मिलने से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मौजूदा नीतियों में कई बदलाव होंगे। पहले से ही पिछले छह महीनों में घरेलू अर्थव्यवस्था के स्तर पर कई बदलाव हुए हैं। यह पत्र वाणिज्य और प्रबंधन पर उनके प्रभाव के संदर्भ में इन परिवर्तनों की जांच करने का प्रयास करता है। साथ ही वैश्विक स्तर पर कई बदलाव हो रहे हैं जिसका असर भारतीय कारोबारी घरानों पर पड़ा है। यह पेपर भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले वैश्विक स्तर पर होने वाले परिवर्तनों का भी अध्ययन करता है। तदनुसार, पेपर निम्नानुसार आयोजित किया जाता है।

खंड (अ) व्यावसायिक पर्यावरण की अवधारणा और भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान परिदृश्य की जांच करता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार प्रक्रिया का परिचय भी देता है।

खंड (ब) घरेलू स्तर पर और वैश्विक स्तर पर कारोबारी माहौल परिदृश्य में बदलाव पर

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

चर्चा करता है।

खंड (स) भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अवसरों और बदलते कारोबारी माहौल के सामने वाणिज्य और प्रबंधन की गुंजाइश का अध्ययन करता है।

मुख्य शब्दः कारोबारी विकास, प्रबन्धन, भारतीय अर्थव्यवस्था आदि।

खंड अः

क) व्यावसायिक पर्यावरण की अवधारणा –

व्यावसायिक वातावरण के कारक मोटे तौर पर दो प्रकार के होते हैंः

1. सूक्ष्म कारक या सूक्ष्म पर्यावरण
2. मैक्रो कारक या मैक्रो पर्यावरण

1. सूक्ष्म वातावरण – यह उस तात्कालिक वातावरण को संदर्भित करता है जिसमें फर्म काम कर रही है। इसमें ऐसे कारक शामिल हैं जिनके संपर्क में फर्म नियमित रूप से आती है और इसलिए फर्म द्वारा आंशिक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। एक फर्म के सूक्ष्म वातावरण में मापदंडों में मूल्य, राजस्व, लागत, रोजगार स्तर, प्रतिस्पर्धी, ग्राहक आदि शामिल हैं। इस प्रकार इसमें वे सभी कारक हैं जिनसे फर्म को दिन–प्रतिदिन के आधार पर निपटना पड़ता है और इसलिए फर्म द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।

2. मैक्रो पर्यावरण – दूसरी ओर, मैक्रो पर्यावरण उन कारकों को संदर्भित करता है जो फर्म के तत्काल पर्यावरण के अलावा हैं। ये कारक न केवल फर्म को बल्कि फर्म के आसपास के आंतरिक वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए, ये कारक फर्म के नियंत्रण से बाहर हैं। चूंकि प्रत्येक फर्म एक बड़ी आर्थिक प्रणाली की एक उप इकाई है, इसलिए, यह मैक्रो कारकों पर नियंत्रण नहीं रख सकती है। इसमें बड़ी सामाजिक और भौतिक ताकतें शामिल हैं जो कंपनी को प्रभावित करती हैं और कंपनी के सूक्ष्म वातावरण में खिलाड़ियों को भी प्रभावित करती हैं। अपरिहार्य सत्य यह है कि परिवर्तन के अनुकूल होने में विफलताय गतिशील मैक्रो अर्थव्यवस्था अनिवार्य रूप से व्यावसायिक विफलता का परिणाम है। एक सफल व्यवसाय वह है जो निर्णय लेते समय इन कारकों में नरम बदलाव का विश्लेषण और व्याख्या करता है। मैक्रो पर्यावरण में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारक शामिल हैंः आर्थिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, कानूनी वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण, जनसांख्यिकीय वातावरण, तकनीकी वातावरण आदि।

ख) भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान परिदृश्य –

भारतीय अर्थव्यवस्था संक्रमण के दौर से गुजर रही है। 1991 से जारी आर्थिक उदारीकरण ने देश को बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर किया है। 2008 तक, भारत ने खुद को दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में स्थापित कर लिया था। 2008–09 में विकास काफी धीमा होकर 6.8% हो गया, लेकिन बाद में 2009–10 में 7.4% हो गया, जबकि इसी अवधि के दौरान राजकोषीय घाटा 5.9% से बढ़कर 6.5% हो गया। वित्त वर्ष 2011 की दूसरी तिमाही के दौरान भारत का चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.1% हो गया, जो पिछली तिमाही में 3.2% था। भारत सरकार के श्रम ब्यूरो के अनुसार, 2012–13 के लिए बेरोजगारी दर, यूपीएस विधि द्वारा देश भर में 4.7% थी और एनएसएसओ विधि द्वारा 3%। भारत की उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 2009–2013 की अवधि में 8.9 से 12% के बीच रही है।

पहली पीढ़ी के सुधार नरसिम्हा राव सरकार द्वारा वर्ष 1991 में पेश किए गए थे और उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की एक लहर की शुरुआत की। भारत में सुधार की प्रक्रिया आर्थिक विकास की गति को तेज करने और गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से शुरू की गई थी। भारत में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया का पता 1970 के दशक के अंत में लगाया जा सकता है। हालाँकि, सुधार प्रक्रिया केवल जुलाई 1991 में शुरू हुई थी। 1991 में ही सरकार ने बाजार की ताकतों पर अधिक निर्भरता, विदेशी निवेश सहित निजी क्षेत्र के लिए एक बड़ी भूमिका, और एक अधिक खुली अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रणालीगत बदलाव का संकेत दिया था।

पिछले डेढ़ दशक के सुधारों ने घरेलू अर्थव्यवस्था को नियंत्रण व्यवस्था से मुक्त करने में एक लंबा सफर तय किया है। भारत के सुधार कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसने तेजी से पुनर्गठन के बजाय क्रमिकता और विकासवादी संक्रमण पर जोर दिया है। भुगतान संतुलन संकट जो निश्चित रूप से गंभीर था, के मद्देनजर जून 1991 में सुधारों को पेश किए जाने के बाद से यह ष्टिकोण अपनाया गया था। हालांकि, यह लंबे समय तक गैर–निष्पादन की लंबी अवधि के साथ एक लंबा संकट नहीं था। 1991 में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने दूरगामी उपायों की शुरुआत की, जिसने अर्थव्यवस्था के कामकाज और मशीनरी को बदल दिया। ये परिवर्तन निम्नलिखित के लिए प्रासंगिक थेः

- औद्योगिक गतिविधि में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व
- औद्योगिक निवेश और क्षमता विस्तार पर विवेकाधीन नियंत्रण
- व्यापार और विनिमय नियंत्रण
- विदेशी निवेश तक सीमित पहुंच
- वित्तीय क्षेत्र का सार्वजनिक स्वामित्व और विनियमन

सुधारों ने भारत की विशाल विकास क्षमता को खोल दिया है और शक्तिशाली उद्यमशील ताकतों को मुक्त कर दिया है। 1991 के बाद से, सभी राजनीतिक दलों की सरकारों ने देश के आर्थिक सुधार के एजेंडे को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है।

भारत में आर्थिक सुधारों के दूसरे चरण में तेजी से व्यापार सुधारों की शुरूआत उसकी विशेषता है जैसे कि मात्रा प्रतिबंधों को हटाना और आयात को रद्द करना, कराधान का युक्तिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र का विनिवेश और सार्वजनिक व्यय का पुनर्गठन आदि। सुधारों में शामिल हैं: अप्रत्यक्ष करों का युक्तिकरण, उर्वरक और खाद्य सब्सिडी में कमी और अंततः चरणबद्ध तरीके से, और अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की हिस्सेदारी को 26 प्रतिशत और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 33 प्रतिशत तक लाना। इसने बीमा क्षेत्र को खोलने, बुनियादी ढांचे में सुधार और दूरसंचार, बिजली, गैस और तेल आदि जैसे क्षेत्रों के पुनर्गठन का आह्वान किया। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा), विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रतिस्थापन सहित, और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) समझौतों के तहत विभिन्न उपक्रमों के कार्यान्वयन द्वारा, बाहरी क्षेत्रों में सुधार शुरू किए गए। ।

वित्तीय सुधारों के लिए मैक्रोइकॉनॉमिक नीतियां क्यों मायने रखती हैं? व्यापक आर्थिक प्रबंधन और वित्तीय विकास के बीच की कड़ी गहरी है और दोनों दिशाओं में चलती है। अनुशासित और पूर्वानुमेय मौद्रिक, राजकोषीय और ऋण प्रबंधन नीतियां वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की नींव बनाती हैं। बदले में, व्यापक आर्थिक नीतियों के प्रभावी प्रसारण के लिए एक अच्छी तरह से काम करने वाली वित्तीय प्रणाली आवश्यक है। हाल के चुनावों में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के भारी बहुमत से भारत की व्यापक आर्थिक नीतियों में बदलाव आया है।

खंड ब: घरेलू स्तर पर और वैश्विक स्तर पर कारोबारी माहौल परिदृश्य में परिवर्तन

मोदी सरकार के पिछले छह महीनों में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नीचे वर्णित हैं:

1) वित्तीय समावेशन – 15 अगस्त 2014 को शुरू की गई प्रधान मंत्री ''जन धन योजना'' को भारी प्रतिक्रिया मिली है। वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित, उद्घाटन दिवस पर, इस योजना के तहत 1.5 करोड़ (15 मिलियन) बैंक खाते खोले गए। 10 जनवरी 2015 तक, 11.5 करोड़ खाते खोले गए, जिसमें लगभग INR8698 करोड़ (US$1-4 बिलियन) इस योजना के तहत जमा किए गए, जिसमें शून्य शेष राशि के साथ नए बैंक खाते खोलने का विकल्प भी है। स्कीम के तहत:

- खाताधारकों को 1 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा कवर ('एचडीएफसी एर्गो' द्वारा दिया जाना) के अलावा, रुपे डेबिट कार्ड के साथ शून्य–बैलेंस बैंक खाता प्रदान किया जाएगा।

- जो लोग 26 जनवरी, 2015 तक 1 लाख रूपये की दुर्घटना के अतिरिक्त खाते खोलते हैं, उन्हें 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर दिया जाएगा (एलआईसी द्वारा दिया जाएगा)।
- बैंक खाता खोलने के छह महीने बाद, धारक बैंक से 5,000 रूपये ओवरड्राफ्ट प्राप्त कर सकते हैं।
- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा शुरू की गई नई तकनीक की शुरुआत के साथ, एक व्यक्ति सामान्य फोन के माध्यम से धन हस्तांतरित कर सकता है, शेष राशि की जांच कर सकता है जो पहले केवल स्मार्ट फोन तक ही सीमित था।
- गरीबों के लिए मोबाइल बैंकिंग नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म (एनयूयूपी) के माध्यम से उपलब्ध होगी, जिसके लिए सभी बैंक और मोबाइल कंपनियां एक साथ आई हैं।

इस प्रकार इस योजना ने संगठित मुद्रा बाजार के क्षेत्र में कई व्यक्तियों को पेश किया है जिससे वाणिज्य और प्रबंधन क्षेत्र, विशेष रूप से बैंकिंग और बीमा के लिए अवसर खुल रहे हैं। यह बैंकिंग उद्योग के लिए भी एक चुनौती है।

2) नीति आयोग की स्थापना – भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय परिदृश्य में सुधार के प्रयास में, योजना आयोग को नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। यह भारत की केंद्र सरकार का एक नीति थिंक–टैंक है जो भारत के योजना आयोग की जगह लेता है और इसका उद्देश्य भारत में आर्थिक नीति–निर्माण में राज्यों को शामिल करना है। यह केंद्र और राज्य सरकारों को रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करेगा। यह सामाजिक और आर्थिक मुद्दों में सरकार की मदद करने के लिए एक आयोग है। भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नीति आयोग बनाने की आवश्यकता पर निम्नलिखित टिप्पणी की–"65 वर्षीय योजना आयोग एक निरर्थक संगठन बन गया था। यह एक कमांड अर्थव्यवस्था संरचना में प्रासंगिक था, लेकिन अब नहीं। भारत एक विविधतापूर्ण देश है और इसके राज्य, अपनी ताकत और कमजोरियों के साथ–साथ, आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इस संदर्भ में, आर्थिक नियोजन के लिए 'एक आकार सभी के लिए उपयुक्त' दृष्टिकोण अप्रचलित है। यह भारत को आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी नहीं बना सकता।''

इस प्रकार नीति आयोग की स्थापना से राज्य सरकारों की भागीदारी में वृद्धि होती है। यह योजना आयोग से एक अलग कदम है जिसमें राज्य सरकारों की भूमिका केवल एनडीसी (राष्ट्रीय विकास परिषद) को रिपोर्ट करने और वार्षिक बैठकों के दौरान बातचीत करने की थी। नीति आयोग के साथ, राज्य सरकार की जिम्मेदारी बढ़ गई है। व्यावसायिक घरानों को बदलते वित्तीय परिदृश्य को ध्यान में रखना चाहिए और नई सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे गतिशील परिवर्तनों के अनुकूल होना चाहिए।

3) ''मेक इन इंडिया'' अभियान – भारत में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने हाल ही में एफडीआई में नए मानदंडों की घोषणा की और ''मेक इन इंडिया'' अभियान के साथ इसका समर्थन किया। यह

बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में निवेश करने और भारत में अपने उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। MNC उत्पादन इकाई की स्थापना से अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन होगा। इससे न केवल रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी।

4) वैश्विक स्तर पर परिवर्तन – व्यावसायिक पर्यावरण भी वैश्विक स्तर पर गतिशील परिवर्तनों को ध्यान में रखता है। भारत–अमेरिका संबंधों में पिछले कुछ महीनों में नाटकीय रूप से सुधार हुआ है क्योंकि भारत ने अपने नीतिगत रुख को बदल दिया है जहां तक एफडीआई मानदंडों का संबंध है। रेलवे में अब 100 फीसदी एफडीआई की इजाजत, बीमा में एफडीआई में बढ़ोतरी, रक्षा क्षेत्र ने विदेशी खिलाड़ियों के लिए दरवाजे खोले, भारतीय कॉरपोरेट घरानों को विदेशी खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा का दबाव महसूस होगा और उन्हें प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा। हाल ही में यूरो संकट निर्यात घरानों के लिए एक चुनौती बन गया है जिनके मेजबान देशों में यूरोपीय राष्ट्र शामिल हैं। उपरोक्त सभी भारतीय अर्थव्यवस्था में हाल के दिनों में देखे गए घरेलू और वैश्विक कारकों में कुछ बदलाव हैं। ये कॉरपोरेट घरानों के लिए चुनौती और अवसर दोनों हैं। बदलते कारोबारी माहौल के अनुरूप अपनी रणनीतियों को अपनाने में कुंजी है।

खंड (स) – भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत और अवसर

भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलते परिदृश्य का अध्ययन करने के बाद, अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्सों की ताकत की जांच करते हैं जो वाणिज्य और प्रबंधन के अवसर पैदा करते हैं –

1) निर्माण क्षेत्र – भारत में अचल संपत्ति क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें आवास की मांग में वृद्धि हुई है। आने वाले वर्षों में, इस प्रवृत्ति के तेजी से बढ़ने की उम्मीद है और यह कॉर्पोरेट घरानों के लिए एक अवसर है।

2) खाद्य उद्योग – एक अन्य क्षेत्र जो बढ़ रहा है, वह है खाद्य खंड, विशेष रूप से रेस्तरां उद्योग। भारतीय अब भोजन के साथ प्रयोग करने के लिए तैयार हैं और एक नए अनुभव के लिए अतिरिक्त रुपये खर्च करने को तैयार हैं। इस प्रकार यह खंड कई कॉरपोरेट घरानों के लिए दरवाजे खोलता है जो खाद्य उद्योग में विविधता ला सकते हैं। साथ ही, क्रय शक्ति और जनसांख्यिकीय लाभांश में वृद्धि के साथ बढ़ती युवा आबादी का संकेत है, इस खंड के आने वाले भविष्य में छलांग और सीमा बढ़ने की उम्मीद है।

3) परिधान– रेडीमेड कपड़े– एक अन्य क्षेत्र जो सकारात्मक मांग पूर्वानुमान दिखा रहा है, वह है वस्त्र क्षेत्र। कई भारतीय ब्रांडेड परिधान खरीदना पसंद करते हैं और वैश्विक ब्रांडों के लिए खुले हैं। साथ ही, आज की युवा आबादी रेडीमेड कपड़ों के पक्ष में झुक रही है, जिससे इस क्षेत्र का दायरा बढ़ रहा है। सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई 100 प्रतिशत होने के साथ इस सेगमेंट में वृद्धि हुई है और भविष्य में भी अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है।

4) इंफ्रास्ट्रक्चर – हाल ही में चुनी गई मोदी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर काफी जोर दे रही है. भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशाल तटरेखा है और इसमें नए बंदरगाहों के विकास की पर्याप्त गुंजाइश है। बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेलवे आदि जैसी ढांचागत सुविधाओं के विकास में सार्वजनिक–निजी भागीदारी की आवश्यकता है। रेलवे में हाल ही में 100 प्रतिशत एफडीआई की घोषणा के साथ, यह क्षेत्र विकास के लिए जबरदस्त क्षमता दिखा रहा है। इसके अलावा, मुंद्रा के पास निजी बंदरगाह निवेश के नए रास्ते खोलते हैं।

5) दूरसंचार – क्रय शक्ति में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क के प्रसार और मोबाइल घनत्व में वृद्धि के साथ, दूरसंचार क्षेत्र में विकास की जबरदस्त संभावनाएं हैं।

6) ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत – सरकार ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को भी बढ़ावा दे रही है और इसके लिए जैव ईंधन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की हाल ही में संपन्न यात्रा ने भी इसके लिए भारत को अमेरिका के समर्थन पर जोर दिया है।

7) शिक्षा – एक अन्य क्षेत्र जहां खुलने की कल्पना की जाती है और व्यावसायिक घराने सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, वह है शिक्षा। भारत में उच्च शिक्षा को विदेशी निवेश के लिए खोलने की चर्चा संसद में लंबित उच्च शिक्षा विधेयक के साथ शुरू हो चुकी है। भारतीय बी–स्कूल विदेशी खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा की उम्मीद कर सकते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारे शैक्षणिक संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के बराबर बनाने के लिए और अधिक निवेश की आवश्यकता है।

8) उड्डयन उद्योग – भारतीय हवाई क्षेत्र के साथ, घरेलू और साथ ही विदेशी खिलाड़ियों के पास विमानन क्षेत्र में भी विस्तार करने का अवसर है। इस सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा तीव्र होने के कारण, कॉरपोरेट घरानों को बेहतर सेवा और ग्राहकों को संतुष्ट रखने के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी।

अन्य क्षेत्र जहां व्यावसायिक घरानों के बढ़ने की गुंजाइश है और पिछले दस वर्षों में पहले ही विकास देखा है, उनमें आईटी और आईटीईएस, मीडिया और मनोरंजन आदि शामिल हैं।

निष्कर्ष – उपरोक्त से, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक सफल फर्म वह है जो बदलते परिवेश, परिदृश्य पर नजर रखती है। जिस दुनिया में हम रहते हैं वह एक गतिशील है, एक गतिशील उद्यमी वह है जो इन परिवर्तनों पर नजर रखेगा। क्लार्क के अनुसार, एक उद्यमी जो गतिशील है वह वह है जो अधिकतम लाभ कमाता है।

फर्मों को तर्कसंगत निर्णय लेने में सहायता करने के लिए, घरेलू और साथ ही वैश्विक नीति परिवर्तनों में परिवर्तनों का ट्रैक रखना उचित है। इन परिवर्तनों पर नजर रखने के लिए, अलग सेल स्थापित किया जाना चाहिए और डेटाबेस को बनाए रखने के लिए सौंपा जाना चाहिए, डेटा को बनाए रखा जाना चाहिए, और फर्मों के नीतिगत निर्णयों पर इसके प्रभावों का अध्ययन करने के लिए इसका विश्लेषण करना चाहिए। इस प्रकार, यह व्यक्तिगत फर्म

की जिम्मेदारी है कि वह मैक्रोइकॉनॉमिक कारकों के परिवर्तनों का रिकॉर्ड रखे और इस तरह बाहरी वातावरण का विश्लेषण करने में फर्म की मदद करे।

संदर्भ

1. Shrieves, R. E. "The relationship between risk and capital in commercial banks". Journal of Banking & Finance, 16(2): 439–457, 1992.
2. Wolgast, M. "M&As in the financial industry: A matter of concern for bank supervisors?" Journal of Financial Regulation and Compliance, 9(3): 225-236, 2001.
3. Al-Tamimi, H. A. H and Al-Mazrooei, F. M. "Banks' risk management: A comparison study of UAE national and foreign banks". Journal of Risk Finance, 8(4): 394-409, 2007.
4. Sensarma, R. and Jayadev, "Are bank stocks sensitive to risk management?" Journal of Risk Finance, 10(1): 7-22, M. 2009.
5. Zhao, T., Casu, B. and Ferrari, A. "Deregulation and Productivity Growth: A Study of the Indian Commercial Banking Industry". International Journal of Business Performance Management, 10(4): 318-343, 2008.
6. Goyal, K. A. and Joshi, V. "Mergers in Banking Industry of India: Some Emerging Issues". Asian Journal of Business and Management Sciences, 1(2): 157-165, 2011a.
7. Fernando, A. C. "Business Environment". Noida: Dorling Kindersley (India) Pvt. Ltd. (2011), pp. 549-553.
8. Gelade, G. A. and Ivery, M. "The Impact of Human Resource Management and Work Climate on Organizational Performance". Personnel Psychology, 56(2): 383-404, 2003.
9. Bartel, A. P. "Human Resource Management and Organizational Performance: Evidence from Retail Banking". Industrial and Labor Relations Review, 57(2): 181-203, 2004.
10. Dev, S. M. "Financial Inclusion: Issues and Challenges". Economic & Political Weekly, 41(41): 2006.
11. Sekaran, U. "Paths to the job satisfaction of bank employees". Journal of Organizational Behavior, 10(4): 347-359, 1989.
12. Mitchell, T R., Holtom, B. C., Lee, T. W. and Graske, T. "How to Keep Your Best Employees: Developing an Effective Retention Policy". The Academy of Management Executive, 15(4): 96-109, 2001.

13. Saxena, N. and Monika, K. "Organizational Culture and its Impact on Employee Retention". Pacific Business Review, 2(3): 102-110, 2010.
14. Levesque, T. and McDougall, G.H.G. "Determinants of Customer Satisfaction in Retail Banking". International Journal of Bank Marketing, 14(7): 12 – 20, 1996.
15. Clark, M. "Modelling the Impact of Customer-Employee Relationships on Customer Retention Rates in a Major UK Retail Bank". Management Decision, 35(4): 293-301, 1997.
16. Clark, M. "The Relationship between Employees' Perceptions of Organizational Climate and Customer Retention Rates in a Major UK Retail Bank". Journal of Strategic Marketing, 10(2): 93-113, 2002.
17. Hansemark, O. C. and Albinsson, M. "Customer Satisfaction and Retention: The Experiences of Individual Employees". Managing Service Quality, 14(1): 40 – 57, 2004.
18. Benedikter, R. "Answers to the Economic Crisis: Social Banking and Social Finance". Spice Digest, New York: Springer. (2011).
19. Goyal, K. A. and Joshi, V. "A Study of Social and Ethical Issues in Banking Industry". International Journal of Economics & Research, 2011 2(5): 49-57, 2011b.